परमिशन देनी चाहिए, चाहे वह बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। लेकिन उनकी बात यह थी कि वहां इनवायरेनमेंट की प्रॉब्लम थी। वहां खदान में जितना नीचे जाएं, वहां बहुत ज्यादा कोयला मिलता था। मैं आपको और साहू जी को बताना चाहूंगा कि डा. मनमोहन सिंह जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी ने 8 दिन पहले निर्णय ले लिया है कि नॉर्थ कर्णपुरा में पॉवर प्रोजेक्ट होगा और यह उस तरह का होगा, जिस तरह उन्होंने कल्पना की थी। उस वक्त हमने नहीं देखा कि वे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, हम इसे क्यों दे दें, इसे कैंसिल कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि देश के डेवलपमेंट के जो सवाल होते हैं, उनमें पार्टी की बात नहीं लानी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जेएमएम हो, चाहे और दूसरी हों। घटना हो गई, तो हो गई। यहां अभी कांग्रेस की सरकार है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। गवर्नर साहब ने 3 दिन प्रयास किया कि यहां 356 नहीं लगे। उन्होंने सबको बुलाया। कांग्रेस ने यह कहा कि हम सरकार नहीं बना सकते। हमारे पास बड़ी संख्या थी, लेकिन हम सत्ता के पीछे नहीं भागे। हमने सत्ता छोड़ दी और कह दिया कि हम सरकार नहीं बना सकते। अभी भी वहां सस्पेंडेड एनिमेशन है। यादव जी, आप कह रहे थे कि वहां लोग मांग रहे हैं, स्टूडैंट्स मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं। आपको कौन रोक रहा है? आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं। जैसा पहले हुआ था कि 3 महीने में सस्पेंडेड एनिमेशन हटा दिया गया, वैसा हो सकता है। लेकिन उसमें जिस तरह सरकार चलाने की और लोगों को साथ लेकर चलने की विल चाहिए, वह रहनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस बहाने आप सबको वहां के डेवलपमेंट के बारे में बोलने का मौका मिला। हम आपको झारखंड के बारे में आश्वस्त करते हैं, वहां जो भी पार्टीज़ हों, जो भी वहां के रहने वाले हों, कि वहां सुविधा देने के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम जो रिजोलुशन लाए हैं, आप उस रिजोलुशन को मान्य कर दीजिए।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Resolution to vote. The question is:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 18th January, 2013 under article 356(1) of the Constitution in relation to the State of Jharkhand."

The motion was adopted.

GOVERNMENT BILL

The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2012

MR. CHAIRMAN: Okay; now, we take up the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2012.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): आदरणीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

"महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधायक पर, लोक सभा द्वारा पारित रुप में, विचार किया जाए"।

सभापति जी, लोक सभा में यह बिल ऑलरेडी 3 सितम्बर, 2012 को पारित किया गया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को उनके कार्य स्थल की जगह पर सुरक्षित माहौल दिया जाए और उनका Sexual Harassment at Workplace रोका जाए। यह बिल एक ऐसा बिल है जो अपने आप में पहली बार लाया गया है और जल्द ही सभा की अनुमति से इस पर ऐक्ट बनेगा। इस बिल का उद्देश्य है कि अपने वर्क प्लेस पर महिलाओं की आजादी सुरक्षित रह सके, वे अच्छी तरह से काम कर सकें, इकनॉमिकली एमपावर्ड हो सकें और जिस उद्देश्य को लेकर वे काम करने के लिए आती हैं, उस उद्देश्य को आराम से पूरा कर सकें।

इसके लिए पहले Indian Penal Code में मात्र कुछ प्रोवीज़न्स ही थे, जैसे Article 354, Article 309 etc. etc., इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइड लाइन्स थीं, जैसे Vishaka Vs. State of Rajasthan, लेकिन यह सब सिर्फ organized sector में था, unorganized sector में नहीं था। इसीलिए इस बिल को इस मंशा से लाया गया कि देश भर में जितने भी working place हैं, चाहे वे organized sector में हों या unorganized sector में हों, महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जा सके, जिससे वे अपना काम-काज अच्छी तरह से कर सकें, और स्वतंत्र रूप से अपनी इकनॉमिकल स्थिति को सुधार सकें।

इसके सम्बन्ध में हमारी Parliamentary Standing Committee के कुछ suggestions और recommendations भी थीं, जिनसे हमें बहुत लाभ मिला है। उनकी एक suggestion और recommendation जो हमें मिली थी, वह यह थी कि इसमें domestic workers को भी रखा जाए, इसलिए इस बिल के अन्दर, जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, उन domestic workers को भी रखा गया है। पहली बार इस तरह का बिल आया है कि केवल सरकारी दफतरों में काम करने वाली महिलाएं ही नहीं, बल्कि जो गैर-सरकारी कार्य स्थलों में काम करती हैं, चाहे वे labour के रूप मं कहीं काम करती हों या unorganized sector में काम करती हों, उन सब महिलाओं को इसमें रखा गया है।

इस बिल के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के सम्बन्ध में मैं आप सबको भी बताना चाहूंगी, जैसे, as proposed under clauses 2(a) and 2(n), the Bll seeks to cover all women, irrespective of their age, employment, status and protects them againt sexual harassment at workplace, at all workplaces, both in public and private sector, whether organized or unorganized.Women who are employed as well as those who enter the workplaces as clients, customers and apprentices, students in all educational institutions, and patients in hospitals are also sought to be covered under this Bill.

इस बिल के अन्दर केवल वर्क प्लेस में काम करने वाली महिलाओं को ही नहीं बल्कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स या किसी भी प्राइवेट शॉप पर काम करने वाली महिलाओं को, जहां पर भी कोई कलाएंट जाते हों, उन सभी को कवर किया गया है।

दूसरा है; the Bill under clause 19 casts a responsibility on every employer to create an environment at every workplace which is free from sexual harassment.

इसी तरह से, as proposed under clause 4, an Internal Complaints Committee is required to be constituted at every workplace under the chairmanship of a senior woman employee, which should comprise of a third party, NGO, etc., as well. On receipt of a complaint, this Committee, as proposed under clause 10, facilitates conciliation between the aggrieved woman and the respondent, if the woman prefers such conciliation. Similarly, under Clause 26, the employer is liable to be punished if he does not act on the recommendations or violates any other provisions of the Bill. इसी तरह से, the District Officer of every district is required, under clause 6, to constitute a Local Complaints Committee for the unorganized sector, headed by an eminent woman and consisting of, at least, half women members with due representation of SCs, STs, OBCs and minority communities to look into any complaint of sexual harassment from workplaces which employ less than 10 workers or when the complaint is against the employer. The Committee also receives complaints from domestic workers. This Committee, like the Internal Complaints Committee, facilitates conciliation if any aggrieved woman so desires and so on. बहुत सारे different clauses, जैसे- Clause 13(3)(ii), Clause 18 इसमें दिए गए हैं। क्लॉज़ 14 में हमने रखा है कि, "However, malicious intention is required to be proved, and the inability to prove the charge shall attract action against the complainant." अगर कोई महिला malacious intention से या *malafide* intention से कोई कम्प्लेन करती है, तो उसके लिए भी थोड़ी-सी पनिशमेंट है, लेकिन अगर वह कम्प्लेन करे परन्तु वह उसको प्रूव न

[श्रीमती कृष्णा तीरथ]

कर सके, तो उसको mala fide intention नहीं माना जाएगा। इसमें हमारा जो क्लियर टाइम लिमिट है, वह 90 days 'for completion of enquiry' है। क्लॉज 11(4) जो है, इसमें the provision is, '60 days for taking action by the employer'. Then, there is the Clause 13(4). ये अलग-अलग क्लॉज़ेज हैं Clause 16, Clause 11(4), Clause 13(4), Clause 12, of Clause 19, Clause 29 which have already been sent to Members of the House.

I think, women would be able to access justice under the provisions of the Bill only when they are aware of the existence of such a law as well as the mechanism available to them. To achieve this objective, responsibility has been given under Clause 19(c) to every employer to organize workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitizing the employee about the provisions of the Bill.

Similarly, under Clause 2 (b), the District Officer is required to take necessary measures for engaging non-governmental organizations for creation of awareness on sexual harassment and the rights of woman.

Both the Central and State Government are mandated under Clause 24 to develop relevant IEC and training material and organize awareness programmes to promote understanding of the public of the provisions of this Bill.

सभापति जी, मैं अपील करना चाहूंगी कि यह जो बिल रखा गया है, यह महिलाओं की सुविधा के लिए है, ताकि उनके वर्क प्लेस पर उन्हें अच्छा माहौल मिले। मैं सदन से अपील करूंगी कि इसको कंसीडर करें और इस बिल को पास करें। धन्यवाद।

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: I have a list of speakers. Dr. Najma Heptulla.

डा. नज़मा ए. हेपतुल्ला (मध्य प्रदेश): सर, हमारी मंत्री जी बहुत ही comprehensive और बहुत मोटा बिल लाई हैं, जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, 30 क्लॉजेज़ हैं, सब क्लॉजेज़ हैं तथा सब-सब क्लॉजेज़ भी हैं। बहुत से सजेशंस है। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह बिल तरतीब किया होगा और मुझे इस बिल पर बोलने के लिए कहा गया है।

सर, पहले तो मैं यह बात कहूंगी कि इस सरकार का हर चीज पर knee-jerk reaction होता है और कोई सोच नहीं होती है। हम ब्लास्ट्स हो गये या टेररिस्ट अटैक हो गया, तो होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट कर दिया कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। यहां एक भयानक

रेप हुआ, दर्दनाक रेप हुआ। मैं उसको क्या कहूं, जो दिल्ली की घटना थी। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश था। दिल्ली में और दिल्ली से बाहर तथा पूरी दुनिया में उसकी डिटेल जब लोगों ने पढ़ी, तो सभी शॉक्ड हो गये कि हमारे कैपिटल टाउन में यह हो रहा है।

यह नहीं था कि हमारे यहां महिलाओं के प्रोटेक्शन या रेप के प्रोटेक्शन के कानून नहीं थे। कानून तो बहुत हैं। हमारी मंत्री जी जानती होंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 48 के करीब ऐसे कानून हैं, जिनका ताल्लुक महिला से है। वे डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं। सर, यह बात मुझे खुद मालूम नहीं थी कि 48 कानून हैं। जब मैं किसी जगह बोलने के लिए गई, तो मुझे पढ़ना पढ़ा, तब मुझे पता लगा कि 48 कानून हैं। मेरे ख्याल में, उस वक्त मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही कानून हैं, अब एक और हमारे सामने आ रहा है।

जब दिल्ली की रेप की घटना हुई, तो सरकार ने एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की कमेटी बनाई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। प्रेजिडेंट साहब ऑर्डनन्स लेकर आए। वे जब दोनों सदनों को संबोधित कर रहे थे, तब हम सब महिलाएं, इधर की और उधर की, हर साल यह उम्मीद करती थीं कि प्रेजिडेंट साहब किसी दिन तो अपने भाषण में, पिछले साल, उससे पहले साल, उससे पहले साल, महिलाओं की सत्ता में भागदारी से संबंधित बिल के बारे में कोई अनॉउंमेंट जरूर करने वाले हैं और हम बड़ी नाउम्मीद होकर यह कहते थे, फिर हाउस में आकर, सर, आपसे पहले जो चेयरमैन थे या पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से कहते थे। सर, सवाल तो यहां यह हो गया है कि सत्ता में भागीदारी तो अलग बात है, प्रेजिटेंड साहब को उसकी हिफाजत के बारे में, उसकी इज्जत के बारे में, उसकी जिन्दगी के बारे में अपने अभिभाषण में कहना पड़ा। यह अफसोस की बात है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कि अगर किसी मुल्क के बारे में जांचना हो, तो उस मुल्क की महिलाओं की क्या हालत है, क्या दिशा है, उससे देखा जाए। आज़ादी के 65 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे प्रेजिडेंट साहब को महिला के बारे में अपने भाषण में बोलना पड़ता है, तो आप मुझे यह बताइए मंत्री जी, सर, मैं आपसे कहती हूं कि क्या कानून थे? दिल्ली की घटना होने के बाद एक हफते के अंदर चार खबरें आईं और इसी दिल्ली के आस-पास की खबरें आईं और हद यह हुई कि नाबालिग बच्चियों के बारे में खबरे आईं। आज आपने हम लोगों को यहां बोलने की इजाजत दी, हम लोग हाउस में बोले, मंडारा में तीन बच्चियों के साथ हुई घटना के बारे में बात हुई। वे तो नाबालिग हैं, मैं उसको रेप, में या बालात्कार में कहना ही नहीं चाहती, मैं उसके लिए कोई वर्ड ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे किसी भी डिक्शनरी में, न अंग्रेजी में, न हिन्दी में और न उर्दू में, कोई वर्ड ही नहीं मिला। दरिन्दगी जिसको कहा जाए, वैसी दर्दनाक हरकतें बच्चियों के साथ होती हैं। क्या कानून नहीं था? क्या हमारा कानून नहीं था? सवाल यह है कि हम कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट तो इसीलिए बनी है कि आप कानून लेकर आएंगे, लॉ मिनिस्ट्री मोटे-मोटे कानून बनाएगी, छोटे-छोटे

[डा. नज़मा ए. हेपतुल्ला]

नहीं, मोटे-मोटे कानून बनाएगी तीस-तीस पेज के, तीस-तीस क्लाउज के, आठ-आठ चैप्टर के, जिनमें बहुत से सजेशंस होंगे, उसमें पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी के बहुत से सजेशंस होंगे। मैं मंत्री जी की नीयत पर जरा भी शक नहीं कर रही हूं, उनकी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन सर, मुझे लगता है कि वे कुछ ज्यादा ख्वाब वगैरह देखती हैं कि कुछ हो जाएगा, मगर थोड़ी रियलिटी के बारे में सोचिए कि इतने कानून होने के बाद, 48 कानून होने के बाद क्या हो गया? आपको क्या उम्मीद है कि आप पूरे देश में कमेटियां बना पाएंगी? क्या आप उनके ऊपर इम्प्लिमेंटेशन कर पाएंगी? सिर्फ कानून बनाने से फायदा नहीं होता है, बल्कि उसकी इम्प्लिमेंटेशन की जरूरत है। अब यह बनेगा। सर, बिल तो पास हो ही जाएगा। इस हाउस में कौन है, जो यह कहेगा कि हम बिल को पास नहीं करेंगे। सभी कहेंगे कि बिल पास करो, यह महिला का प्रोटेक्शन है। बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा, फिर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए रुल्स बन जाएंगे और हो सकता है कि जो कानून है, वह छः महीने के अंदर यहां पर आ जाए, उसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाए, मगर क्या उस कानून का इम्प्लिमेंटेशन हो पाएगा या वे रूल्स लागू हो पाएंगे? मुझे इस पर शक है।

सर, मैं यहां पहली बात यह कहना चाहती हूं कि मुझे इसके टाइटल पर ऐतराज है। आपने इसको लिखा है, 'The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill'. मंत्री जी, हम इतनी ज्यादा सेक्स-सेक्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्या औरतों को सिर्फ सेक्सुअली हरैसमेंट ही होता है, जहां वे काम करती हैं? क्या वहां उनका फिजिकल हरैसमेंट नहीं होता या उनका मेंटल हरैसमेंट नहीं होता? क्या वहां उनके साथ बदसलूकी नहीं की जाती या क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता? इसमें सेक्सुअल हरैसमेंट लिखने की क्या जरूरत थी? आप इसमें हरैसमेंट लिखते। अगर औरत को किसी भी तरह का हरैसमेंट होता है तो you cannot bring every harassment under 'sexual harassment'. अगर उसको मेंटरली हरैसमेंट है, तो क्या आप उसको सेक्सुअल हरैसमेंट कहेंगे? अगर आपको जेंडर आइडेंटिफिकेशन करना था, तो इसमें वुमैन तो लिखा ही हुआ था। अगर इसको आप और आइडैंटिफाई कर रहे थे, तो आप इसको जेंडर के लिहाज से कर देते। आप इसको जेंडर हरैसमेंट कर देते। मैं यह कैसे मान लूं कि हरैसमेंट सिर्फ महिलाओं के साथ होता है? अगर किसी का बॉस पुरूष होगा, तो आप कहेंगी कि महिला के साथ उसने हरैसमेंट किया, लेकिन अगर कोई महिला बॉस है और वह एक महिला का हरैसमेंट करे, तो वह तो सेक्सुल हरैसमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर वह पुरुष के साथ भी हरैसमेंट करेगी, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? शायद वह पुरूष के साथ हरैसमेंट करेगी, तो वह सेक्सुअल हरैसमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, मगर यदि कोई महिला किसी महिला को हरैस करेगी, तो आप उसको किस कानून के अंतर्गत लेंगी?

आपने जो कमिटियां बनायी हैं, उनमें आपने खास तौर पर यह प्रोविज़न रखा है कि उन कमिटियों की चेयरमैन महिला होगी। आप सरकारी संस्थाओं की बात कर रही हैं, आप इसको वहां इम्प्लिमेंट कर दीजिए। आज सारी महिलाएं सरकारी नौकरी तो नहीं करती है, बल्कि आज महिलाएं कॉल सेंटर्स में भी काम करती हैं। कॉल सेंटर्स में काम करने वाली महिलाओं के लिए आप इस कानून को कैसे इंम्प्लिमेंट करेंगी, क्योंकि उनका कितना हरैसमेंट होता है, यह तो आपको मालूम ही है? प्राइवेट सेक्टर या कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर एक एचआरडी (हयूमन रिसोर्स डेवलमेंट) डिपार्टमेंट होता है, जो इस तरह की किसी भी कम्प्लेंट, चाहे वह किसी महिला की हो या पुरूष की हो, की रिड्रेसल के बारे में सोचता है। इसको प्राइवेट सेक्टर्स में इम्प्लिमेंट कराने के लिए आपके पास क्या जरिया है? उसके ऊपर कंट्रोल करके, उसके ऊपर विजिलिएंस रख कर आप उसको कैसे देखेंगी और उसके लिए आपके पास क्या हथियार है, इस बारे में आपने इस बिल में कहीं जिक्र नहीं किया है। क्या यह जरूरी है?

आपने कहा, जहां 10 से ऊपर लोग काम करते हैं, तो वह इस बिल के अंतर्गत आ जाता है। मान लीजिए, आपके घर में 10 लोग होंगे, अरुण जी के घर में भी 10 हो सकते हैं और मेरे घर में भी 10 होंगे, तो फिर उसको आप कैस इम्प्लिमेंट करेंगी? इसको कौन-सी एजेंसी इम्प्लिमेंट करेगी और कौन गवाही देने वाला होगा? आपने इसमें डमेस्टिक का क्लॉज़ डाला है, तो उस डमेस्टिक के लिए इम्प्लिमेंटेशन का क्या तरीका होगा? आप उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइएगा, तो मैं समझती हूं कि हो सकता है कि कन्वींस हो जाऊं। वैसे मुझे कन्वींस होने की उम्मीद नहीं हैं, क्योंकि इस बिल को मैंने चार-पांच बार पढ़ा है। मुझे माया जी ने कल ही कहा कि आपको इसे पढ़ना है, तो मैं रात के दो बजे तक इसको पढ़ती रही। मैंने सोचा कि इसमें मुझे कुछ तो अच्छा दिखे? आपने तो इसमें सभी कुछ कवर कर दिया। वास्तव में, इसमें अब हम लोगों के बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि It's like a banyan tree, जिसके अंदर आपने सारे क्लॉज़ेज डाल दिए हैं, सारी चीज़ें डाल दी हैं, मगर कहीं भी आपने यह नहीं लिखा कि इसकी इम्प्लिमेंटेशन के बारे में आप क्या करने वाली हैं।

आपने कमिटियों की बात कही। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। इस बिल का ताल्लुक केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होगा। जो भी अत्याचार होते हैं, वे स्टेट्स के अंतगत आते हैं। आप स्टेट में कौन सी मशीनरी बनाएंगे कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप इम्प्लीमेंट कर सकें? क्या यह बिल लाने से पहले आपने उस स्टेट की महिला मंत्रियों की कोई मीटिंग रखी, महिला के विभाग से ताल्लुक रखने वाले मंत्री चाहे पुरुष हो या महिला हो या चीफ मिनिस्टर से बात करी कि हम इस तरह का लेजिस्लेशन ला रहे हैं? तो यह लेजिस्लेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, यह स्टेट गवर्नमेंट के लिए ग्रास रूट तक है, गांव तक है, गांव तक है, जिसका आपने इसमें जिक्र किया है। फिर क्या आपने उनको कांफिडेंस में लिया? आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम लोगों से बिल पास करा लेंगी, लेकिन उसको वहां तक,

[डा. नज़मा ए. हेपतुल्ला]

ग्रास रूट तक कैसे लेकर जाएंगी? कौन एजेंसी होगी जो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कमेटियां बनाएगी, आपके पास क्या मकेनिज्म है सेंट्रल से स्टेट में जाकर कमेटी बनाने का? क्या मकेनिज्म आपने सोचा है? हमारे यहां पंचायतें हैं। गांव की पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटीज़ हैं और हमारे यहां एक फोर टॉयर सिस्टम है, डैमोक्रेटिक सेटअप है। आज पंचायत में तकरीबन पूरे हिन्दुस्तान में 50 परसेंट महिलाएं चुनकर आती हैं। क्या हम यह काम उस पंचायत को नहीं दे सकते थे कि पंचायत कर ले? अब यहां भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर के सुपुर्द कर देती हैं। अब मैं कहना नहीं चाहती हूं कि पंचायतें तो फिर भी जवाबदेह होती हैं। वह गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसका नाम इसमे लिखा है, जिसके ओहदे के बारे में आपने लिखा है, क्या आपको लगता है कि वे सही ईमानदारी से काम कर पाएंगे और उनके ऊपर क्या विजिलेंस होगी? फिर आप कहती हैं एमिनेंट लोग हों, जो काम करें। अब गांव में कौन से एमिनेंट लोग आप ढूंढेगी, एमिनेंट की क्या परिभाषा है? आप में या जो हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठी हैं, हम लोगों तो जरूरत ही नहीं है, हम अपने हुकूक को जानती हैं। We are one who have flown over the cuckoo's nest. सो हमें इस बिल की इतनी जरूरत नहीं है। मुझे तो आज तक भी किसी ने ह्रासमेंट नहीं किया किसी भी तरक का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं जवाब दे सकती हूं और उल्टा ह्रास कर सकती हूं। मगर जो औरत अपना पेट भरने के लिए मजबूर है नौकरी करने के लिए, क्या उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वह ऑफिसर के पास जाकर अपने एम्प्लॉयर के बारे में शिकायत करे। मैं बड़ी कम्पनी की बात नहीं कर रही हूं, मैं गांव की बात कर रही हूं, क्योंकि ह्रासमेंट एक्च्युअली वहां होता है, जहां उसकी जुबान नहीं है, वह बोल नहीं सकती है। मंत्री जी, थोड़ा दोबारा से सोचिए। बिल पास करना हमारी जिम्मेदारी होती है। हम बिल तो पास कर ही देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। मगर क्या होगा, ऐक्ट बन जाएगा।

(उपसभाध्यक्ष (श्री तिरुची शिवा) पीठासीन हुए)

ऐक्ट बनने के बाद उस पर एक्शन की जरूरत है। यह सरकार तो इन-एक्टिव है। यहां तो कोई एक्शन ही नहीं होता खाली रिएक्शन होते हैं। टेरेरिज्म हुआ, जैसे मैं कहा, होम मिनिस्टर ने आकर बयान दे दिया। होम मिनिस्टर साहब बदलते रहते है, बयान नहीं बदलते। टेरेरिस्ट की एक्टिविटीज होती रहती हैं, बम का धमाका चाहे मुम्बई में हो, पूना में हो, नागपुर में हो, हैदराबाद में हो, बेंगलुरु में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, होम मिनिस्टर आकर कहेंगे zero tolerance. मिनिस्टर बदल गया, उनकी लेंग्युएज नहीं बदली, उनका बयान नहीं बदला। तो इस तरह की इन-इफेक्टेवनैस है। दो हुए थे, दो से बीस हो गए, बीस के अंदर आपने जीरो लगा दिया zero tolerance. अब तो यह बिल आने से मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ी zero telerance सरकार के खिलाफ दिखाना चाहिए कि कोई tolerance की, हर चीज

की हद होती है। इसी तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। यही बात कही जाती है zero tolerance against अत्याचार against women. Zero tolerance atrocities against women. हम रेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम औरत का मर्डर बर्दाश्त नहीं करेंगे और करते जा रहे हैं। वह कहावत है कि अब के मारवो तो हम भी मारवो। जहां तक कमेटियों का सवाल है, सर, आपसे इजाजत लेकर मैं हिन्दी में बोलूंगी, आप translation सुन लीजिए।

मैं कमेटी की एक बात बताऊं। तो 80 के दशक में जब मैं यहां चुनकर आई, तो जस्टिस हिदायतुल्ला साहब हमारे चेयरमैन थे। इंदिरा गांधी जी हमारी महिला प्रधानमंत्री थीं। हम लोगों ने Constitution Club में एक skit की उस skit में मैंने एक वाक़िआ सुनाया था। यह मैं without prejudice to any Parliamentary Committee, any former Chief Justice Committee, any judges Committee, without prejudice to anybody, बता रही हूं। मैंने एक बात मज़ाक़ में कही, लेकिन वह बहुत दूर तक गयी। यह बात मैंने former Chief Justice, Chairman Rajya Sabha के सामने और former Prime Minister इंदिरा गांधी जी के सामने कही। मैंने कहा एक बार जहांगीर बादशाह बहुत दुखी थे। उनके वज़ीर ने पूछा कि आप क्यों दुखी हैं? तो बादशाह ने कहा कि मेरी मल्लिका नूरजहां ने घोबी को गलती से मार दिया। अब मेरा इंसाफ तो कहता है कि मैं उसे सज़ा दूं। तो उनके वज़ीर ने कहा कि यह तो बड़ा आसान मसला है। आप यह मामला एक कमेटी के सुपुर्द कर दीजिए। इस पर बादशाह ने पूछा कि अगर उस कमेटी ने भी वहीं फैसला दिया जो मैंने दिया, फिर क्या होगा? वज़ीर ने कहा कि आप Joint Parliamentary Committee बना दीजिए। बादशाह ने पूछा कि अगर Joint Parliamentary Committee ने भी वहीं कहा तो क्या करेंगे? उस पर वज़ीर ने कहा कि, हुजूर आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस की कमेटी कायम कर दीजिए। इस पर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं कब तक ये कमेटियां कायम करता रहूंगा? तब उनके वज़ीर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कहूं, जब तक धोबन मर न जाए। तो यही हालत कमेटियों की होती है। जिस मसले को मारना हो, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी हो, उसे एक कमेटी के सुपुर्द कर दीजिए। उसके बाद उस पर कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि उसे कमेटी देख रही है। अब जब कमेटी देख लेगी, अपनी रिपोर्ट दे देगी तब उस पर अमल होगा। इसलिए मंत्री जी यहां सवाल एक्शन का है। आज यहां बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा, लेकिन मुझे नही लगता कि इस साल में इसके ऊपर कुछ असर होगा। जब हमारे गणमान्य राष्ट्रपति जी अगले साल हमारे दोनों हाउसेस में अपना अभिभाषण देंगे तो सरकार की उपलब्धियों में एक बिल यह भी शामिल हो जाएगा। उसका नतीजा कुछ नहीं होगा। वह सिर्फ पेपर के ऊपर आ जाएगा। इसके साथ-साथ मैं यही कह सकती हूं कि आप यह बिल बड़ी उम्मीदों के साथ लायी हैं, मगर आप शायद ख्वाब में हैं। उन ख्वाबों की ताबीर होती मुझे दिखायी नहीं दे रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चेयर का शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

डा0 प्रभा ठाकुर (राजस्थान): महोदय, मैं सदन की बहुत सीनियर सदस्या डा0 नज़मा जी को बहुत ध्यान से सुन रही थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री महोदया ने इस बिल के बारे में बहुत गंभीरता से विचार किया है। महोदय, मैं Women Empowerment Committee की भी सदस्य हूं और इस बारे में हमारी कमेटी की तरफ से भी जो सुझाव दिए गए, उन्हें आपने इसमें शामिल किया है और मंत्री महोदया ने इस बिल को काफी मेहनत से तैयार किया है। उसके पीछे सरकार की और मंत्री जी की मंशा यही है कि महिलाओं को उनके कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से निज़ात मिले। हालांकि नज़मा जी कह रही थीं कि इस मामले को व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर बालिकाओं से लेकर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के इतने मामले घटित हो रहे हैं कि यह एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। इसलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केवल यौन उत्पीड़न तक सीमित रहकर इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है।

महोदय, मैं इस विधेयक के लिए मंत्री महोदया की नीयत और भावना का स्वागत करती हूं और विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी ओर से न केवल सांसद होने के नाते बल्कि एक महिला होने के नाते कुछ बातें रखना चाहती हूं।

महोदय, आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह के अपमानजनक व्यवहार, इतने भयानक, भीषण, अपराध, भेड़ियों की तरह सामूहिक बलात्कर के समाचार सुनते हैं और बच्चियों के साथ इस तरह के बलात्कार होते हैं, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। क्या ऐसा अपराध हत्या से बढ़कर बड़ा अपराध नहीं है? कई बार मेरी अपनी समझ में यह नहीं आता। मैं इस समय केवल एक राजनैतिक दल की सदस्य होने के नाते नहीं बोल रही, बल्कि एक औरत होने के नाते भी बोल रही हूं। चाहे सरकार बीजेपी की हो, एनडीए की हो, यूपीए की हो, चाहे अधिकारी कहीं के भी हों, उनके ट्रांसफर होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, आते-जाते रहते हैं, मगर उनकी सोच पुरूष प्रधान समाज होने से अपनी होती है। महिलाओं के प्रति जो उनकी शुरूआत से सोच है, लगता है वह सोच, वह व्यवस्था गांव से लेकर शहर तक, विधान सभाओं से लेकर संसद तक, पंचायत से लेकर संसद तक सब जगह, कहीं न कहीं अपना एक प्रभाव रखती है। जैसे पुरुषों को अपने घर की बहन या बेटी, मां या पत्नी सम्मानजनक लगती है, अगर वहीं भावना हमारे देश के पुरूषों के मन में सभी के प्रति आ जाए, यानी औरों की बहन बेटियों के प्रति भी उतनी ही गंभीरता आ जाए, तो हमें यहां खड़े होकर भाषण-बाजी करने की जरूरत नहीं रहेगी, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए भी इतने कानून बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके लिए सही नीयत होनी चाहिए।

महोदय, मैं विधि मंत्री महोदय से भी जानना चाहूंगी, गृह मंत्री जी से भी पूछना चाहूंगी कि पिछले तीन वर्षों का आप मुझे बता दें कि जहां किसी कार्य-स्थल पर किसी महिला के साथ कोई यौन उत्पीड़न संबंधी व्यवहार हुआ, वहां क्या किसी को सजा मिली है? आप जानकारी मंगवा कर देख लीजिए, हो सके तो कृपया मुझे भी वह जानकारी भिजवा दीजिए,

4.00 P.M.

ताकि हम भी सदन को बता सकें। हौंसलें क्यों बुलंद होते हैं? यह दामिनी जैसे कांड क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? उन्हें मालूम है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ना। इस अदालत से सजा होगी, तो वहां दूसरी अदालत से छूट जाएंगे और वहां से होगी तो आगे जाकर छूट जाएंगे। कोई पैसे के दम पर, कोई प्रभाव के दम पर, कोई जाति और समाज के दम पर सोचते हैं। इस तरह की सोच से इस देश में महिलाएं कब तक भुगतती रहेंगी? सरकार या सरकारें क्यों इस बात पर इतना लंबा विचार करती रहेंगी कि इसकी सजा क्या हो? मुत्यु दंड की सजा क्यों न हो? मौत की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? जब किसी का सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसमें कौन से एवीडेन्स की जरूरत है? वह लड़का जो दामिनी के साथ था, क्या उसका शिनाख्त कर लेना और एक मेडिकल रिपोर्ट का आना काफी नहीं है? क्यों नही उन लोगों को वही सजा होनी चाहिए? अगर ऐसी सजा होती, तो उसके बाद जो कांड हुए हैं वे नहीं होते और आगे कांड नहीं होते। इसका जल्दी से जल्दी प्रावधान किया जाए। क्या मिडल ईस्ट में आदमी, मर्द नहीं रहते? वहां औरतें नहीं होती? वहां उनको क्यों संयम रहता है? इसलिए, क्योंकि वहां ऐसी सजा है कि फौरन इंसाफ होगा और सजा-ए-मौत होगी, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए किसी का वहां ऐसा हौसला नहीं होता। हमारे यहां कार्य-स्थल पर महिलाओं को मजदूर से लेकर उच्च-स्तर अधिकारी तक से यह समस्या रहती है। वे क्या करें? किस-किस को खुश करें? कितने मामले मेरे सामने आए, जब मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही तब भी, आज इस कमेटी की सदस्य हूं तब भी ऐसे मामले सामने आते हैं। प्रमोशन के दौरान उन्हें परेशानी आती है। अगर कोई किसी पर केस करती है, सवाल उठाती है, शिकायत करती है, तो उस अधिकारी का बहिष्कार करके बाकी पुरुष अधिकारी उस लड़की का या उस औरत का साथ दें, उसके बजाय सब उसको हरेस करने के लिए एकसाथ हो जाते हैं। उसको निकाल बाहर करने के लिए ताकि आगे से कोई दूसरी औरत सिर उठाने की या खिलाफ बोलने की जुर्रत न करे। क्या करें औरतें, इधर जाएं तो कुआं, उधर जाएं तो खाई। कई घरेलू मजबूरियां होती हैं, कैसे छोड़े नौकरी? कई महिलाओं के लिए नौकरी करना जीवन-मरण का प्रश्न होता है, तो क्या करें? बेबस होकर सब कुछ चुपचाप सहती रहें? कितनी महिलाएं हैं, जो अदालतों तक पहुंचती हैं, हिम्मत करती हैं? कौन देगा उन्हें हिम्मत, कहां हैं उनके पास इतने आर्थिक संसाधन, सामाजिक हिम्मत? वे बदनामी के डर से चुप रहती हैं, कोई एक-दो परसेंट हौसला करके पहुंचती भी हैं, तो क्या होता है, अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं?

उपसभाध्यक्ष जी, एयरफोर्स की पायलट अंजलि गुप्ता ने जब अपने से बड़े अधिकारी की शिकायत की, तो क्या नतीजा हुआ? नतीजा यह हुआ कि वहां बैठकर सारे अधिकारियों ने उसी का कोर्ट मार्शल किया, एक महिला का कोर्ट मार्शल किया। बड़ी मुश्किल से किसी महिला ने सेना में जाने की हिम्मत की। इसका क्या परिणाम हुआ? आखिर में उस लड़की ने फांसी

[डा0 प्रभा ठाकुर]

लगाकर अपनी जान दे दी। यह व्यवस्था है। जब अंजलि गुप्ता, एयर फोर्स के एक बड़े अधिकारी के सामने आती है, किसी IAS या किसी बड़े अधिकारी के बारे में अखबारों में खबर आती है, तो आप सोचिए कि मजदूर महिलाओं की क्या स्थिति होगी? वे महिलाएं जो बहुत ही छोटी-मोटी नौकरियां करती हैं, जिनके सामने सवाल है कि उन्हें अपने बच्चों को पालना है, अपने परिवार को चलाना है, उन्हें कैसे इस समस्या से निजात मिलेगी?

उपसभाध्यक्ष जी, हम जब महिलाओं को अधिकार देते हैं, तो टुकड़ो मे देते हैं, जैसे टुकड़े फेंक रहे हों। अगर उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना है, तो गोवा में इसके लिए कानून है। मैं गोवा गई थी, मुझे वहां पता चला। यहां गोवा के भी सांसद हैं, आप उनसे पूछिए, क्यों नहीं आप उस मॉडल को adopt करते? यह कहा जाता है कि - "यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" और दूसरी तरफ मैथिलीशरण गुप्त जी लिख रहे हैं कि-

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध और आंखों मे पानी।"

तो कौन सी कहानी सही है? जब चाहे देवी, जब चाहे दासी, व्यवहार दासी का। घर में उत्पीड़न, बाहर उत्पीड़न, काम पर जाओ, तो उत्पीड़न। आखिर इस देश की क्या व्यवस्था है? यह जो मानसिकता है, यह मानसिकता कानून बनाने में भी reflect होती है। हमारी महिला मंत्री महोदया यह विधेयक लाई हैं। इन्होंने पूरी मेहनत की है। अब यह कानून बनेगा, इसमें भी कुछ रह जाएगा। आप बता दीजिए कि अब तक बलात्कार के मामलों में कितने लोगों को क्या सज़ा हुई है? क्या छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या के बराबर, नहीं हैं? क्या यह हत्या से ज्यादा जघन्य अपराध नहीं है? जहां पर सामूहिक बलात्कार की स्थिति है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की स्थिति है या घर के ही किसी पारिवारिक रिश्तेदार के द्वारा बलात्कार किया गया है, उसे हत्या के समान समझकर आखिर सज़ा-ए-मौत की सज़ा क्यों नहीं दी जाती? यह मेरा नहीं, पूरे देश का मत है। सबके घरों में बहन-बेटियां हैं और सबको उतनी ही प्यारी हैं। जिस पर बीतती है, वही जानता है। जिसकी हत्या हो जाए, वह तो एक बार मर जाता है, लेकिन बलात्कार की शिकार वह लड़की जिंदगी भर तिल-तिलकर मरती है, उसके परिवार के लोग मरते हैं और उनका उस मोहल्ले में रहना दूभर हो जाता है, क्योंकि आज ये हालात हैं और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है।

मेरा यही निवेदन है कि हमारे यहां कानून तो खूब हैं, लेकिन अगर जनता को कानूनों का लाभ नहीं मिलता, तो यहां रोज कानून बनाने का फायदा क्या है? इन कानूनों का फायदा वे लोग ले जाते हैं, जो अपनी मरजी से जैसा चाहें उन्हें ट्विस्ट कर लें, कमेटियां अपनी मरजी से जैसी चाहें रिपोर्ट बना लें। इसलिए उनका पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसलिए उत्पीड़ित महिलाओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें वकील दिए जाएं।

कहने के लिए आप कह देते हैं कि वकील हम available करा देते हैं। महिलाओं को वकील नहीं मिलते हैं। अगर कोई गरीब महिला है, वह कोई वकील नहीं कर सकती हैं, तो उसे वकील उपलब्ध कराया जाए। साथ ही आप बिल में एक प्रॉविजन यह भी करें कि जो लड़कियां, चाहे प्राईवेट कम्पनी में या निजी कम्पनी में या सरकारी में, जिसमें भी काम करें, अगर शाम को 6.00 बजे के बाद उनको ऑफिस से घर जाना है, तो उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, उस संस्था की होनी चाहिए, उस कम्पनी की होनी चाहिए, उस आर्गनाइजेशन की होनी चाहिए। विधेयक में पेज नम्बर तीन पर उप धारा (ड) मे लिखा है "शारीरिक सम्पर्क और फायदा उठाना"। इसके बजाय इसमें यह हो जाए तो अधिक स्पष्ट हो जायेगा- "शारीरिक सम्पर्क द्वारा किसी गरीब औरत की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाना"। "लैंगिग पक्षपत की मांग या अनुरोध करना" की जगह पर "पक्षपात की मांग या किसी प्रलोभन का दबाव डालकर मजबूर करना" होना चाहिए। यह और ज्यादा सख्त हो जाए, तो अच्छा रहेगा। इसमें सज़ा भी सख्त होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस सदन में एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है कि जो कानून बने हैं, उनका लाभ जनता को मिले। उसकी एक समय-सीमा सुनिश्चित होनी चाहिए। औरतों के मामले में फैमिली कोर्ट बन गये, आयोग बन गये, थाने बन गये, पुलिस बन गई, लेकिन एक समय-सीमा में उनको न्याय मिलना चाहिए। जहां पर यह नज़र आ रहा है कि बलात्कारी कौन है, वहां पर तो 30 दिन के अंदर न्याय मिलना ही चाहिए। जहां पर हत्या की जाती है, वहां पर तो फांसी की सजा का ही प्रावधान हो, उसके लिए सजा-ए-मौत का ही प्रावधान होना चाहए जिसने हत्या की है।

इस बिल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपकी जो भावना है, उसकी मैं कद्र करती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि इस कानून के प्रावधानों को पढ़कर ही लोग डर जायें। कुछ एक-दो लोगों के ऊपर तो ऐसी बिजली गिरे, कुछ दो-चार को तो सख्त सज़ा मिले जिससे दूसरों के हौसले बुलंद न हों, वरना कानून कोई भी बनाये, किसी भी सरकार में बने, किसी भी राज़ में आये, उन कानूनों का लाभ जब तक पीड़ितों को नहीं मिलेगा, हमारी बहनों को नहीं मिलेगा तब तक उन कानूनों के बनने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आज पूरे देश में,पूरे समाज में मांग है कि महिलाओं को संरक्षण मिले, महिलाओं की हिफाज़त हो क्योंकि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में शारीरिक दृष्टि से कमजोर होती हैं। महिलाओं के लिए रात में अकेले निकलना वैसे ही दुष्कर है। इसलिए इस समय में यह विधेयक बहुत जरूरी है। इसकी कानून बनने के बाद पूरी अनुपालना होना जरूरी है। जो महिलाएं खुद वकील नहीं कर सकती हैं, उन्हें मदद मिलनी चाहिए। मैंने महिला आयोग को भी देख लिया है। मैंने महिला आयोग में खुद चिट्ठियां लिख-लिखकर देख लिया है, कुछ नहीं हुआ, कुछ होता ही नहीं है। मैंने कब चिट्ठी लिखी, यह अलग बात है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहती हूं कि होता कुछ नहीं है, बाद में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि महिला आयोग से फिर कोर्ट जाओ, इसलिए पहले ही कोर्ट में जाओ। फिर कोर्ट्स में घूमते रहो, वर्षो तक न्याय

[डा0 प्रभा ठाकुर]

पाने के लिए इंतजार करो, जजों की मेहरबानी पर रहो, कानून की मेहरबानी पर रहो और उसके बाद भी पैसे और समय गंवाकर अपना सा मुंह लेकर घर बैठ जाओ। इस व्यवस्था में कोई बदलाव हो, इस सोच में कोई बदलाव हो और इसके बारे में सारा सदन गंभीरता से सोचे। अगर महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, तो उनको आर्थिक, राजनैतिक और समाजिक रूप से सशक्त करने के लिए, सबको पूरे मन के साथ, जैसे अपनी बहन-बेटी के हित के लिए सोचकर कदम उठाते हैं, वैसे ही कदम उठाना होगा, वैसे ही सहयोग करना होना। आपके इस विधेयक के लिए मैं आपको साधुवाद देती हूं और समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

DR. T.N. SEEMA (Kerala): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. Sir, I rise to support the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2012. Sir, it is a very important legislation which is going to give confidence to crores of working women in this country. Sir, we know that atrocities and crimes on women are on the rise in the country. We have been witnessing many cases of sexual offences around us, and we have been witnessing continued denial of justice to thousands of sexual harassment crime victims in our country. Sir, I would like to share the anxiety expressed by Dr. Najmaji and Dr. Prabhaji about the implementation of these kinds of laws in our country. Sir, we know that the implementation side is very poor. Unless we ensure proper implementation of laws, what is the use of bringing more and more new legislations? So, I would like to start my speech with that point.

Sir, this is a very good Bill, but it is unfortunate that women in this country had to wait for a long period of 15 years for this legislation, after the Supreme Court judgement on Vishakha vs. Rajasthan Government. This thing happened in 1997. So, for 15 years, we had been waiting for this legislation, which should be noted. So, that kind of delay should not happen in cases relating to women's legislations. Sir, I take this opportunity to salute the brave woman, Bhanvari Devi, from Rajasthan, a very ordinary *saathin*, who was gang-raped by the upper caste goons. But she fought very bravely with the help of Vishakha and other organizations. Sir, on behalf of the working women in this country, I would like to express my gratitutde to the hon. Supreme Court for giving women in this country a strong weapon to fight for their right at work.

Sir, there are many positive aspects in this Bill. Because of time constraint, I

am not going into the positive aspects. I would like to highlight some of the gaps, some of the weaknesses in this Bill. I would like to appreciate the Government for including the unorganzed sector in this Bill, I think, before going to the Standing Committee, the unorganized sector was not included, but it is included now. But i would like to know about the methodology of implementation of this Act in the unorganized sector. I think, a proper mechanism should be there when we handle this kind of legal protection for the unorganized sector.

Sir, the women staff in the Armed Forces and police services, women students and staff of all schools and educational institutions must also be expressly included under the Bill. In the unorganized sector, the restriction about the number of workers to less than ten should be done away with. The Bill needs to be amended to rectify these weaknesses and loopholes.

Sir, I strongly object to the inclusion of Clause 14 which allows for penal action against the complainant in the Bill, which will defeat its very purpose. How can any law begin on the premise that a complaint may be malicious or false? This seems to codify the age-old prejudice against women and institutionalizes it. The women organizations had repeatedly asked for the removal of the 'complaint with malicious intent' Clause. This not only goes against the Vishaka guidelines, which explicitly state that the complainant should not be victimized in any way, but also completely undermines the victim's ability to file complaints of sexual harassment.

Sir, the Standing Committee also noted this aspect. The women victims of sexual harassment at workplace are in an extremely vulnerable position. As a woman activist, my experience has been that in many of the cases allegations of falsehood and malicious intent are invariably levelled against them. Hence, this clause must be removed from the Bill. Sir, the Bill seeks to give preferred treatment to the accused by protecting his identity. While the identity of the complainant need not be known, there is no reason to extend this protection to the accused otherwise these incidents would not even come to light. Sir, there are many laws for protecting marginalised groups, weaker sections, women, SCs/STs, etc. in our country but majority of these sections do not enjoy the legal protection because of poor implementation, lack of awareness and the gender system on the part of the legal system and police system which are supposed to be the champions or supporter or helper in the

[Dr. T.N. Seema]

implementation of this kind of legal protection. Sir, as Justice Verma Committee Report has stringently criticised the Government's Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition an Redressal) Bill, 2012, I would strongly suggest of referring this Bill to a Select Committee which in consultation with the existing Vishaka complaint ICCs, women's group and other stakeholders for substantial redreafting of the Bill. I would also requesting the Government to make further coordinated efforts with all the Ministries having a crucial role in the implementation of this law so that crores of working women in this country can work and live with more confidence and dignity. Once again, I am supporting the Bill. Thank you, Sir.

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, I rise to support the Bill. There is no question that it should not be supported. But I have some doubts about the possibility of its being properly implemented. The experience that we have regarding the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 shows that law is almost a non-starter. Sir, 19 States have no scheme for implementation of that Act, four States have no separate budget for it. Lack of uniformity and transparency in budget is a severe hindrance to the effectiveness of the Act. Now, it is very simple for any ruling establishment under pressure of public opinion to promptly go through a legislation and to think that it is enough for them to discharge their moral as well as legal obligation to the electorate. But what happens thereafter? I full support this Bill, but what has happened to the Domestic Violence Act? How many cases have been filed How many cases have resulted in conviction? What has happened to the original complainants? Are they still part of the family or thrown out? No one knows anything about it. So, while fully supporting it, I only suggest that now the Panchayats have, at least, 33 to 50 per cent women members; at the Gram Panchayat level women members should be given the power of vigilance and action under this Act as well as under the Domestic Violence Act. Otherwise there will be no case from any of them. Therefore, Sir, I would, through you, ask the Government to have a relook at the whole thing and do not depend on the same statutory Collectors, Sub-Collectors, *Thanedars*, etc. They will be there under the Criminal Procedure and IPC but they need to be supplemented and they can be supplemented only through civil power. That is why the women already in Panchayats should be fully empower to do this.

I have another point to make. I am deeply grateful to hon. Member, *Heptullaji*, for adding to my knowledge that 48 Acts are already in existence pertaining to women. I did not know this. I thought there are only 25 or so Acts. I have been in civil services for 36 years. I have, now, been in the public life for quite some time. I never knew that there are 48 such Acts. I suggest that there should be three separate courts for women cases- one for civil matters, one for matrimonial matters and one for all other criminal matters. But don't touch the IPC. Let the IPC remain what it is. These are all additionalities to the IPC. The IPC does not cover many other things that we have been talking about. So, may I request the Government, through you, to seriously consider for having three types of courts for the protection of women - civil, matrimonial and criminal.

With these words, I wholeheartedly support this Bill.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I rise to support the Bill. I also congratulate the hon. Minister for bringing forward this much -awaited Bill because it has been a long way since we supported and ratified the CEDAW. After the Vishakha Judgement we saw that in spite of the guidelines laid down by the Supreme Court in the Vishakha case, it was seen that it was not adhered to by the agencies that were supposed to adhere to these guidelines. Of course, last but not the least, it reaffirms confidence in women that their fundamental rights, that is, right to live, and not just live but right to live with dignity, and right to parties any profession or occupation or trade, stand strong.

On the one side, we see that we formulate several policies and encourage women to become equal partners in reaping fruits of development in our country, but, on the other side, we see that ever time a step is taken forward by way of policy for letting women come forward, there is a problem that the women face by way of several issues that need to be addressed. Therefor, the point that there are already too many laws, I think, may not stand strong footage because every time there is a new problem and we have to abate the problem. Therefore, laws and legislations need to be made in that direction. It is the unfortunate Delhi incident that really propelled to let out the steam out of citizens about what is happening to women, especially with regard to their safety.

We see that women, in their lifetime, have a horizontal canvass. One is at

[Shrimati Vandana Chavan]

home that has lately been addressed by the Domestic Violence Act, the second is at work place which is being addressed through this Bill, and the third is at public place which, I feel, needs to be taken up in the near future to, probably, make policies. Laws may not be necessary, but policies certainly to make cities and towns gender-friendly so that women feel safe. I am very happy to see that there were a lot of organizations that were saying that domestic workers have not been covered in the initial draft that was made. It is very heartening to see that this section of the society, which is the most vulnerable section, has now been covered and, therefore, the law, in its whole entity, addresses various sections of society.

I would like to point out one section which really worries me and, that is, clause 14, that Madam has also addressed to. It is punishment for false or malicious complaints and false evidence. We have to take into consideration that when a woman makes a complaint she thinks thousands times because it is her credibility and her honor that is at stake and, therefore, it is very rare that a women would make a false complaint. The second issue that we need to take into consideration is that the Internal Complaints Committee and the District Complaints Committee are both run by almost non-legal entities. Of course, it needs a provision that they may or could have a person who has experience in social work or has a legal knowledge. As far as the Local Complaints Committee is concerned, it says, "Preferably have a background in law or legal knowledge." Take for example, in both these committees, a person with legal expertise is not taken and that committee is working as if it is a civil court, following all the procedures laid down by the Civil Procedure Code. In that case, Sir, it will be very difficult for that particular committee to appreciate the evidence that has come forward and then to bring that lady under the malicious complaint which has been filed. I also want to bring to the notice of the hon. Minister that already, there exists a law. Chapter XI of the Indian Penal Code relates to false evidence and offences against public justice. There are several sections which make giving false evidence and fabricating false evidence punishable, and it is not just simple punishment but it is seven years' punishment. So, I feel this kind of a provision, where, while trying to give protection to a woman, you are also keeping a Damocles' sword in front of her, will be as good as creating a fear in her mind that she may file a case, but, then, probably, she might have to face this kind of a charge

that the complaint is malicious. So, this itself will keep her away from filling that complaint. Sir, I would also like to bring to your notice a survey which has been conducted in this respect. This survey was conducted by the Centre for Transforming India, a non-profit organisation. It says that among 600 female employes working in IT sector across India, 50 per cent reported to have been subjected abusive language, physical contact or superiors seeking sexual favour. About 47 per cent did not know where to report this. About 91 per cent did not report for fear of being victimised. So, this is the position of women in our society. Therefore, that the victim fears reporting a crime itself speaks volumes of the reality of the Indian women. Therefore, I seriously feel that the hon. Minister should give consideration to deleting this clause to give more teeth to this specific legislation. I would also like to bring to the notice of the hon. Minister, through you, Sir, as *Najmaji* rightly said, that it is fine that this legislation has mentioned 'sexual harassment' in its title itself, but in future, probably, the word 'harassment' should be continued. I would like to cite an example. Take for example, an employee calls a woman for a cup of tea and she does not go. He may take that amiss and start harassing her. This law itself allows a woman to get compensation if she is in a mental trauma, suffers pain, emotional distress, loss of career opportunity, etc. Under this condition, if she is undergoing mental trauma just because she did not accede to that invitation, he does not fit under any of those sub-clauses. There are no physical contact and advances. There is no demand or request for sexual favours. There is no making of sexually-coloured remarks. There is no showing of pornography. There is no other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature. So, he does not fall under any of these clause, but, at the same time, she is being subjected to harassment just because she did not accede to that invitation. Therefore, I feel, Sir, maybe, this law gets passed at this point of time, but in future, even harassment of woman should be made punishable and that would really make the legislation even stronger.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Actually, it should be dropped. It is not necessary that every time we talk about sex, sex, sex.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Absolutely. As far as implementation is concerned, Sir, there are two, three things which I would like to bring to the notice of the hon. Minister. One, clause 4(1) talks constitution of an Internal Complaints

[Shrimati Vandana Chavan]

Committee. It shall be constituted at all administrative units where the offence can take place. Actually, the NCW in the draft Bill circulated by the Ministry of Women and Child Development, suggested that wherever the offices are located in different places, as far as possible, that Committee should be provided. It is very difficult to find the kind of people that we are expected to put on that Committee. NGO representation is also another aspect. NGOs or associations committed to the cause of women have to be the members of this Committee. Sir, as far as the Economics Census of 2005 is concerned, there are at least six lakh establishment that employ ten or more people. Now where do we find those kind of NGOs? There is no data-base on NGOs, but with our experience as elected representatives, we see that, probably, those kind of members of NGO's may not be available. Thirdly, Sir, people with legal background should be a must in every Committee and, therefore, that kind of amendment, or, possibly, in future, that kind of change, needs to be made.

Another very glaring gap which I would like to bring to the notice of the hon. Minister is regarding clause 2(g). Clause 2(g) defines 'employer'. Amongst the various categories of 'employers', sub-section (iv) says 'in relation to a dwelling place or house, a person or a household who employs ..., This is for the domestic worker. As per Clause 2(o) 'workplace', even includes, in sub-section (vi), a dwelling place or a house. Now, Sir, Chapter VI talks about duties of an employer. That means, even all these people, who are employing domestic workers, are bound to follow the duties of employers. And what are the duties of employers, Sir? Clause 19 says, 'every employer shall (a) provide a safe working environment at the workplace which shall include safety from the persons coming into contact at the workplace.' It is fine. Then, I come to clause 19(b). Sir. this is where, I think, is some gap or anomaly which needs to be addressed. It says, "Display at any conspicuous place in the workplace, the penal consequences of sexual harassments; and the order constituting, the Internal Committee under sub-section (I) of Section 4,' Sir, that means, in every house where a domestic worker works, it is expected by law that we need to put a plate saying that 'this is my duty and there is a complaint committee to which the domestic worker can get access to.' Under the duties of employer, in 19(c), it also says, 'organize workshops and awareness programmes ...' Sir, now this is again not possible for a household which has a domestic worker working there.

Sir, I feel it would be the duty of the Government for which there is another clause 24 which says that it will be the duty of the Government along with NGOs to create awareness amongst women and domestic workers as to what would amount to sexual harassment.

Sir, these are a few points and gaps which I feel need to be addressed. All in all, it is an all-pervasive legislation. I would also look forward in future that women safety is addressed to in public space. Especially, after the incident in Delhi, women safety has become a major issue. In the city which I come from, Pune, we have moved a policy where we are trying to make Pune a gender-friendly city. The simple thing like having glass doors to elevators just creates a feeling of security and safety to a woman. We have several metro stations underground or subways where having some shops itself makes you feel that you are safe in a subway. There are several such steps which needs to be taken to make sure that women are safer in public life and public spaces also.

Thank you very much, Sir, for giving me a patient hearing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Ms. Vandana Chavan, for your impressive maiden speech. Now, Dr. Ashok Ganguly.

DR. ASHOK S. GANGULY (Nominated): Sir, I am very pleased to rise to support this Bill. Harassment of women in India is now not only a national shame but also a national burden. This Bill is part of a series of actions that need to be taken to publicise and kept on the front burner, if it is not going to end up like so many past legislations which were supposed to protect women in India.

I think, one of the landmark Bills which has had a very major impact, especially, at the workplace is the Whistle blower Act, which defines the 'whistle blower'. More importantly-as somebody has said about false accusation and harassment- I think, women who complain about sexual harassment, wherever it might be, need a Women Complainant Protection Act also.

I request the hon. Minister, through you, Sir, to consider this as a special provisions so that women can come forward more readily, and not be afraid of being harassed after they go back to the workplace. I think the fear of harassment and embarrassment is a major issue that we cannot underestimate. We have to make a

[Shri Ashok K. Ganguli]

start somewhere, although, this is not a solution to the problem. And this is not only a problem of India; it is a global problem. It is not going to be solved tomorrow or the day after. You have to build up the bricks that eventually become a social shame for the people and a country who do not change the basic measures to protect 50 per cent of its population.

Since it is a Bill for protection of women at the workplace, I think it should be made compulsory, hon. Minister, for Annual Reports of Companies to have a section on incident of sexual harassment of women, the status about what the company has done during the previous year, as we require them to do for safety, as we require them to do for minority shareholders, etc. It should clearly describe as to what they have done. I think this should be made compulsory. The hon. Minister may kindly request that this be incorporated in the proposed Companies Act.

Secondly, a lot of women who now work in shifts, especially in the BPO sector and the IT sector, and even in certain manufacturing sectors are provided with transportation after certain hours. The transport companies, transport contractors, etc., have to be certified and they should have their police records updated, periodically so that when there is harassment, or, when there is a complaint, such persons can be traced and action taken. This is now becoming compulsory, for example, for buses which deliver children to schools, Major crimes that take place even after dusk and early morning are by transport contractors and drivers and their associates who get involved in it.

Thirdly, I think there must be both special and mobile courts like ambulance are there to carry I the injured or there are mobile pharmacies in remote places. There have to be mobile courts, staffed by women, where women complainants and not be afraid of the surroundings and the social stigma that comes with complaining about harassment at a workplace, whether it is in rural India or whether it is in urban India, because normal policing is not going to be able to implement what is intended in this act.

So, I request the hon. Minister, through you, Mr. Vice-Chairman, to kindly consider the availability, the visibility of instruments of delivering justice and succor to women who suffer silently whether under domestic circumstances or in public

places or at their workplaces. You have begun a campaign. This campaign is going to build up; it is going to take years to have any impact at all. We are very grateful to be a part of this group in order to support you in whichever way we can because this is a problem of national shame and burden which we must deal with in an uncompromising way. I thank you, hon. Chairman.

DR. BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Sir, when I support the Bill and my party supports the Bill, I do it with a pinch of salt. However, this Bill is very well intended, but it is a very naive exercise, or, perhaps a very hus-hush exercise, a hurriely-done exercise without good homework. Even if this well intended Bill is passed, it will only remain a piece of legislation. I don't think that it will come as a help to women, especially those who are working. That are you going to achieve by passing this Bill? The provisions in the Bill are already there in many existing legislations. Here, we are talking only about women. Here woman is a central point and, therefore, we are doing this. In clause 2, you say about 'workplace'. As per this clause, 'workplace' includes government offices, private sector companies, NGOs, hospitals and so on and so forth. We have forgotten to put multi-national companies in this. They come here and operate here. Don't they come under Indian laws, or, can we say that they are foreign companies and they can behave the way they want? It is not so and even the Government does not seem to think so. But it happened because we have not done the homework properly. Another thing is 'harassment'. Najma*ji* and Vandana*ji* have rightly pointed out about it. The Bill defines the 'sexual harassment'. Some five points have been given here. I don't want to repeat them. Is that the only trouble that women employees face while working in cities like Mumbai and Delhi or even in remote places? Is that the only thing? 'Sexual harassment', when it comes to physical, is one part of it. There is much more than sexual harassment which is happening all over the places. Take, for example, promotion. While giving promotion, there are complaints. As a person working in public domain and earlier as a journalist, I used to get complaints that being a woman she is neglected while getting promotion. Doesn't it come under this Bill? As per your definition, it doesn't. But it should be there. Now I come to another very simple thing. There are employees in a company, small or big; there are industrial or commercial establishments where men and women work. In my opinion, if this law has to be in

[Dr. Bharatkumar Raut]

force, there should be a special provision for women employees as far as their wash-rooms are concerned. In many places, it is not so. What do you do about it? We have to specify all these things in this Bill. Sir, I know some companies in Mumbai and Delhi where there is an unwritten but well-obeyed and well-followed rule that women should not be employed beyond this level. I can give you ten examples. Isn't it sexual harassment? In my opinion, that is the biggest sexual harassment. Here you are negating an opportunity to a women. But that is not mentioned in this Bill because no homework is done here in this Bill. And, these are reputed firms; forget about smaller firms. They say that if they employ women, they will have to give them maternity leave, they have to give them transport after certain hours; so why take the *jhanjhat*, and they don't employ women. If this is the situation in India, then only mentioning 'sexual harassment' does not cover everything.

Sir, there are some businesses, some sort of jobs which go 24x7. For example, people in call centres, medical profession, journalism, media and telephone operators work round the clock. In these jobs, we cannot have any system by which we can say that only woman will come for 'X' hours and they will not work beyond 'X' hours. But, it so happens that in some establishments, because women have to be provided transport in the evening, they are restricted to certain period of time and they are denied work during rest of the time. (Time-bell rings) So, here also, we have to say the same thing. Sir, I will take only two minutes more.

Another thing is that in this Bill, we are holding only employers responsible for many things. I am not employers' representative. But I think it would be unjustified and, therefore, it will not stand in the court of law when we hold employer responsible for certain things, for example, a place where a woman employee, or a male employee, is in constant contact with outsiders, like journalists come in contact with outsiders very regularly. If one of the outsiders makes some advances or makes some comments about a women employee in an office, as per this law, the employer is held responsible. How can you hold the employer responsible for the behavior of an outsider? This is a small thing that I have told you. But, what do you do in the case of a ticketing clerk in airlines? Here, social education is very necessary. But, this Bill has been brought only to save face, and, therefore, I think, a better exercise would have brought a much better Bill. I wish the

hon. Minister, after getting the Bill passed, would go back, do the home work properly and will come back with a better Bill.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Odisha): Sir, I rise to support the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2012. I am very much grateful to the hon. Minister that she brought this Bill. I also thank Dr. Manmohan Singh, the Prime Minister, and the UPA Chairperson, Mrs. Sonia Gandhi, who have brought this Bill before the Parliament for the protection of women workers at workplace.

Sir, at the outset, I must clear that this is a Bill to protect the women workers at workplace. So, there is a difference between women being sexually harassed or abused in any other place and women workers being sexually harassed or abused in a workplace. That must be understood very clearly. Some people were asking here as to what was the necessity to mention the word 'sexual harassment'. It is necessary because in our country, we have around 49 Acts, industrial employment standing orders and service conditions to take care of other harassments at the workplace, but to address the issue of sexual harassment, it was very much necessary to mention the words 'Sexual Harassment of Women at Workplace' in the title of the Bill. For this also, all trade unions, including INTUC, were demanding to bring this Bill. The International Labour Organisation Building and Woodworkers International and the international community were also putting pressure to bring this Bill. At the outset, I would also like to thank the Government for bringing this Bill in a proper shape before the Parliament. As it has been said, there are many issues which have to be taken up. We have cases where higher officials also harass the workers. We had a case of a Chairman of a Public Sector Undertaking, NALCO, harassing a woman in a big hotel in Mumbai for giving her promotion. Later on, he was suspended, and, ultimately, he was dismissed. There are many incidents. I want to draw your attention to a shocking incident which happened last Tuesday, "A 15-year-old girl from a family of poor workers from Assam was raped by manager Chintu Singh. When the matter came to light, the owner, Ramchandra Singh, offered Rs. 500 to the girl's family and suggested a compromise, sub-divisional police officer M.K. Choudhary told the Hindu. Mr. Choudhary said the labourers were beaten up when they voiced their protest. The manager's two aides, Deepak Singh and Satish Kumar Singh, have been arrested for abetment. However, Chintu Singh has escaped

[Shri Rama Chandra Khuntia]

across the border to Nepal." This is the incident of a worker of brickklin in Bihar. This is not the only incident; there are thousands of incidents which occur all over the country. We just had an incident of *Nirbhaya*, which took place in Delhi. We know the incident of rape and murder, which happened in Pipli in Odisha. We know the incidents of rape and murder, which happened in Maharashtra, Rajasthan, Bihar, UP and many other places.

Some people are saying that we have the law of the land but whether it will be implemented. The question is whether it is a case of general harassment, or, rape, or, rape at a Workplace, or, sexual harassment, whether we are sincere to implement these laws. Who are the people responsible to implement these Acts? We all have to think over it very seriously. Everybody is pointing fingers and showing figures to the Government or the political party, whichever political party it may be. But, I want to ask a question. If the law is not implemented in the country, is the society civil servant, media or judiciary also not responsible for that? How many cases, rape cases, murder cases, are pending in the courts, and, who has to take a decision? Why is the judiciary not taking decisions? Why has the judiciary not disposed of the cases? Can the judiciary also assured to the general public that the rape cases, murder cases or sexual harassment cases, which are pending in the courts, will be disposed of within two years? If the case is disposed of and the culprits are punished, definitely, all the people will be afraid of the law and will not commit any offence. You may pass a number of legislation in the Parliament but in the name of deferment of the court dates, in the name of absence of witnesses, the cases will be deferred, and, the poor woman, who has been raped or sexually harassed, will continue to be deprived of justice. We cannot afford to have this situation. It may so happen, as Madam also gave an example, that till the young woman become old and dies in her remote village, the case will not be disposed of.

Now, we have to take to task each and everybody in this country. It is a matter of great shame. We feel proud that this is a country of *Sita*, this is a country of *Anusuiya* but, in this country, the women are being raped on the street and we are all silent spectators! We only blame each other. If it happens in Delhi, we blame the Central Government. If it happens in a State, we blame the State Government but what are we doing. The first question that we have to decide in this country is

whether we can dispose of all the murder or rape cases within a stipulated time of two years. Within one year or two years, such a case must be disposed of, and, the culprit must be punished. I think, that is the first thing, on which we should take a decision.

The second thing is as to why these murder, rape or harassment cases are happening. You go to a cinema hall, 80 per cent of people are male. You go to a bus, 80 per cent of travelling people are male. You go to the aeroplane, you go to the train, 80 to 90 per cent of the travelling people are male; hardly ten to twenty per cent of them are female. In Army also, we have millions of soldiers but only one thousand of women. That is the main reason for harassment. If out of one thousand IAS officers, five hundred are women, if in the Army a minimum of twenty thousand or thirty thousand are women officers, if in cinema halls fifty per cent are women, if in Rajya Sabha, in Lok Sabha, in State Legislatures the number of women are more, I think, nobody will dare to harass or rape women in this country. Are we working for that? They were talking about the employers. I think, the most discriminatory part is that private employers do not want to employ women because women will take maternity leave, women will not be willing to work after six and because sometimes there is also apprehension, as you were telling, that a woman may make a complaint for something. Not only sexual harassment alone, if an employer, whether a Government corporation or the Central Government, is denying employment to a woman on gender bias, they should also be liable to be punished. On gender bias, if anybody is refusing employment, that is also an offence because that is also discrimination against the women.

Sir, I want to mention here one thing. It has been mentioned in clause 9 of this Bill that the complaint has to be filed within three months. I think that is also not correct. Today, I read in the newspaper, and it is a major of great shame, that after nine years, punishment was given to a father who had raped his daughter. This is the thing that is happening. so, if you say that the complaint has to be made within three months, a woman can even be confined for three months so that she does not make the complaint. The workers may be threatened, the officers may be threatened. She may not be able to make the complaint within three months and you say that after three months, her complaint will not be taken into consideration. I think this is not fair. I think there should not be any time limit for making the

5.00 P.M.

[Shri Rama Chandra Khuntia]

complaint, especially for women. Also, clause 26 talks about the punishment for the employer. Ganguly *sahib* was also mentioning about the punishment for the employer. It seems that we do not want to punish the employer. The employer is liable by the law to comply the provisions of the law. If the employer is knowingly not complying with the provisions of the law, he or she is liable to be punished. Here, you are keeping fifty thousand rupees as punishment. I think, we should also add imprisonment for six months or one year or something like that. Punishment of fine is not a big punishment. We know that many employers are very good employers. As a trade union leader, I have come across many employers who are very good employers. But there are also some bad employers, like some workers can also be good and some of them can also be bad. Now, the question is, if the punishment is lenient, the employers may not be that interested to comply with all the provisions of the Act. So, my request would be, if the hon. Minister can also consider adding six month imprisonment or one year imprisonment with the punishment of fine of fifty thousand rupees, it would be more beneficial for the women workers.

If you go through the details, I can give you an example, it is not only the case in the ILO. It happened in Singapore and other countries also. In a developed country like Singapore, they are also trying to hide the sexual harassment case at workplace. One woman organisation pressurized the ILO and ILO made a survey which says that sexual harassment is common at the workplace. The survey says, "Out of 272, 54 per cent in 92 companies had experienced some form of sexual harassment at workplace".

And, 12 per cent had received the threat for termination in case they made a complaint to the employer or higher authority or the Government. So, this is the Report of the ILO and it is going on. In this case, if you look at America, the sexual harassment law in America is also very strong. Sexual harassment is an illegal form of sexual discrimination under American Civil Rights Act.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Khuntia, one minute please. I would like to take the sense of the House. If the House agrees, we could continue this debate and finish off this Bill. There are 4-5 speakers.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHUARY: Let us complete this.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Sir, we can complete this. I am concluding.

श्रीमती माया सिंह: (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, डिबेट आज कनक्लूड करा लीजिए, मिनिस्टर साहिबा का रिप्लाई कल हो सकता है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: आज ही करा दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): I think the reply will be very short. Okay, the House agrees to continue.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: So, they have a formal policy which prohibits sexual harassment at workplaces. They have made a policy. As a result, if we look at the situation in the USA, cases of sexual harassment have been reduced to a greater extent. In 2001, the number of cases of sexual harassment was around 15,000. Now, it has been reduced to around 11,000. That means, a strong law for sexual harassment has yielded good results in the USA. We must expect that if this law is implemented properly, we can also get better results. So, we all must understand that this is not a situation just of workplace or outside. The issues of women are coming up in this country and it is our joint responsibility to respond positively to resolve those issues. I think, we full support this Bill and we also expect that judiciary, media and all the people in the society would support it so that the culprits can be punished at the right time. I think, punishing the culprits and creating an opportunity to make 50 per cent space for women in the work place and society, in the service, in the employment and everywhere will give a handle to resolve the issues of women in this country. Thank you.

श्रीमती माया सिंह: उपसभाध्यक्ष जी, हालांकि मेरा गला खराब है, लेकिन मैं जितना बोल पाऊंगी, उतना बोलने की कोशिश करुंगी। आज महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2012 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, इस विधेयक को बनते-बनते 13 साल गुजर गए। लैंगिग उत्पीड़न हमारे समाज की एक दु:खद वास्तविकता है और आज जब हम सदन में इस चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे जो पूर्व के अनुभव हैं, हमें उन अनुभवों से भी कुछ सीखना होगा। अभी तक महिलाओं के लिए जितने भी कानूनों का प्रावधान हुआ था या कानूनी संरक्षण पर अगर हम नजर डालते

[श्रीमती माया सिंह]

हैं, तो हमें पहले वही पर्याप्त लगते थे, लेकिन जिस तरीके से देश में रोज घटनाएं घट रही हैं और खासतौर पर दामिनी का जो केस हुआ, उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जब हम महिलाओं के संरक्षण संबंधी कानूनों पर नजर डालते हैं, तो हमें हर कानून पंगु नजर आता है। हमें यह विचार करना होगा कि क्या हम ठीक से कानून नहीं बना पा रहे हैं या फिर अगर हम ठीक से कानून बना रहे हैं, तो क्या उनके क्रियान्वयन का तंत्र लचीला है? यदि वह भी ठीक है, तो समाज में जागरुकता लाने के लिए हमारे जो भी प्रयास होने चाहिए, कोशिशें होनी चाहिए, वे नहीं हैं?

मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि हमारी संसद को और जो हमारी नौकरशाही है, उसको प्रभावी रुप से इस पूरे विषय पर समग्र रूप से विचार करना होगा कि क्या महिलाएं अत्याचार का शिकार होती रहेंगी और अत्याचारी कानूनों में खामियां ढूंढकर, निकालकर महिलाओं पर अत्याचार करते रहेंगे और संसद में हम इसी तरीके से चर्चा पर चर्चा कराते रहेंगे, यह ठीक नहीं है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने इस विधेयक को पढ़ा है। इसमें महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़न के संबंध में महिलाओं के जो कार्यस्थल की परिभाषा दी गई है, उसकी विस्तृत परिभाषा की विवेचना की है और हर क्षेत्र में काम करने वाली महिला का इसमें ध्यान रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें शिक्षा के क्षेत्र में और प्रोफेशनल क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को यदि हम देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको पूरी तरह से इस विधेयक के माध्यम से संरक्षण दे पायेंगे या नहीं दे पायेंगे, यह मुझे खुद को संशय होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो शिक्षक हैं या छात्र संबंधी मामलों में भी बहुत सी बालिकाएं हैं, बहुत सी बच्चियों का शोषण हो रहा है और उन्हें ठोस कानून के अभाव में न्याय नहीं मिल पाता है। उदाहरण के तौर पर डाक्टर्स हैं, प्राइवेट नर्स हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट के रुप में काम करने वाली महिलाएं हैं, ये महिलाएं तो किसी के साथ नौकरी से संबंधित नहीं हैं, ये अलग-अलग क्षेत्रों में काम रही हैं, लेकिन कार्यस्थल पर जो इनके सहयोगी होती हैं, भागीदार होते हैं, उनके साथ कई बार इनको असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी इनकी गरिमा को बहुत ठेस पहुंचती है। फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम करने वाली जो बहनें हैं, उनमें से कई बहनों से मैं भी मिली हूं, उनको भी अपने क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि उनको हम इस विधेयक के माध्यम से संरक्षण दे पायेंगे या नहीं दे पायेंगे, इस पर मुझे संशय होता है, क्योंकि आपने इसमें सेक्सुअल उत्पीड़न के लिए जो कमेटियां गठित की हैं और कमेटियों को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हमें इस उपबंध को और स्पष्ट करना होगा। स्पष्ट करने से मेरा आशय है कि जो महिलाएं हैं वे स्वयं भी, अपनी इच्छा से इस फोरम में आ सकें। बिल के अध्याय दो में आंतरिकत परिवाद

समितियों के गठन की जो बात कही गई है, उसमें आतरिक परिवाद समिति जब अपनी रिपोर्ट दे देती है, तो उस पर नियोक्ता को सिर्फ दंडात्मक कार्यवाही करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। वह समिति जो अपनी रिपोर्ट दे देगी, लेकिन सर्विस रूल्स के हिसाब से नियोक्ता को कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसे फाइन है, ट्रांसफर है, डिमोशन है, संस्पेंस है या बर्खास्तगी, तभी इस विधेयक का उद्देश्य सफल हो पायेगा।

इसी तरीके से अध्याय तीन के बिंदु पांच में है, जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को कार्यवाही के लिए शक्तियां दी गई हैं। इसमें भी संशोधन की मैं आवश्यकता महसूस करती हूं। यदि इसमें श्रम आयुक्त को हम शामिल कर देते हैं, तो इससे महिलाओं को ज्यादा संरक्षण मिलेगा। इसी तरीके से मैंने देखा है कि आपने आंतरिक परिवाद समिति बनाने की बात कही है, उसमें व्यवहारिकता है कि 10 कर्मचारियों से कम के कार्यालय जहां-जहां हमारे पास हैं या संस्थाएं हैं, तो वहां पर आंतरिक परिवाद समिति बड़ी मुश्किल से बन पायेगी, हम कैसे इनको बनायेंगे? जहां पर हमारे कार्यालय में 10 से कम कर्मचारी हैं, वहां पर ये समितियां कैसे गठित होंगी? दूसरी बात यह है कि आंतरिक परिवाद समिति को आपने सिविल कोर्ट की शक्तियां दी हैं, उनको ताकत दी है और उनमें सदस्यों की कानूनी जानकार होने की बाध्यता नहीं है तथा न ही किसी सदस्य को कानूनी प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। ऐसी स्थिति में, मुझे संदेह होता है कि समिति न्याय कैसे करेगी और यह संशय मेरे मन में पैदा होता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूं कि क्या हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि महिला आयोग, श्रम आयुक्त और स्थानीय प्रशासन, कुछ समय के अंतराल पर एक समीक्षा-बैठक जिला स्तर पर करे, जिसमें उस जिले में कार्य स्थल पर जाने वाली महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए अगर कुछ बातें संज्ञान में आयें तो उनकी समीक्षा भी हो सके। इसलिए मैं यह चाहती हूं कि जो अनुच्छेद-20 में जिला अधिकारी को, कर्तव्य शक्तियों को जोड़ा गया है, तो अगर हम उसमें इसको भी डाल सकते हैं तो यह एक अच्छा और सख्त कानून बन सकता है। इसी तरीके से जहां तक असंगठित क्षेत्रों की बात है, इस विधेयक को असंगठित क्षेत्र के लिए प्रभावी बनाने के लिए, जहां श्रम आयुक्त नहीं हैं, वहां इसके लिए कोई ठोस प्राधिकरण होना चाहिए। उसके पास श्रम कानूनों के प्रावधान के तहत कार्यवाही करने का अधिकार हो। मैं चाहती हूं कि इस तरह की बात इसमें होनी चाहिए।

महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना ही सुझाव देना चाहती हूं कि जैसा कि मुझ से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के केस से यह विधेयक अस्तित्व में आया है। यह विधेयक महिलाओं को समाज में संरक्षण दे और सिर्फ कागजों और चर्चाओं में ही न रहे। हम चाहते हैं कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह बिल भी अपने पूर्व बिलों

[श्रीमती माया सिंह]

की भांति क्रियान्वयन के स्तर पर निष्प्रभावी न हो जाए, इसलिए इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है, यह विधेयक जिस Sexual Harassment को रोकने की बात कर रहा है, तभी कहीं जाकर यह सार्थक हो पाएगा। माननीया मंत्री जी ने इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए या कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए जो प्रयास किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Andhra Pradesh): Sir, I welcome this Bill and congratulate the hon. Minister for bringing this legislation before this House. It is an important legislation which protects women against sexual harassment at workplace, since gender-based violence is one of the forms of discrimination that seriously inhibits women's ability to enjoy rights and freedom on the basis of equality with men.

Article 11 of the U.N. Convention on CEDAW talks about what constitutes sexual harassment. But this recommendation, to which India is a party, was given way back 1992, that is, 20 years ago. And, it is unfortunate that it is becoming law here after two decades! Anyway, it has come now, and I am thankful to the hon. Minister for bringing this Bill. Secondly, Clause 2(n) defines what constitutes sexual harassment. But, if you look at sub-clause (v), it says, "any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature" would constitute sexual harassment. This clause appears to be vague as it does not clarify what constitutes' unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct.' I request the hon. Minister to clarify this. Secondly, eve-teasing in our country is the most common practice and girls at schools and colleges are victims of this. I had gone through the Bill to find out whether eve-teasing constitutes sexual harassment. But, nowhere in the Bill has it been mentioned that eve-teasing constitutes sexual harassment. The hon. Minister only copied whatever Supreme Court has prescribed in the Vishaka case. I think the Government never thought about other forms of sexual harassments. So, I request the hon.Minister to include 'eve-teasing' as sexual harassment under Clause 2(n) of the Bill.

The second point I wish to make is that the Bill has kept out domestic workers working at home. Sir, there are 47.5 lakh women registered as domestic workers in the country. And, if you take into account the unregistered women

domestic workers, it runs into a few crores. Most domestic workers are poor, illiterate, unskilled and come from vulnerable communities and backward areas. Now, I think, after a lot of persuasion, the hon. Minister agreed to include all domestic workers under Clause 2(e) of the Bill. But, Sir, what about those who constitute five to seven times of registered domestic workers? The Bill deprives them access to an efficient redressal mechanism in getting protection from sexual harassment. The purpose of this Bill is defeated if they are not included, because they constitute a large chunk, larger than any other woman group. So, I request the hon. Minister to find a mechanism so that they are also covered under this. The Bill does not make it clear if the recommendations made by the Local Committees under Chapter III are binding and have to be mandatorily implemented by the employer. I request that recommendations of the Local Committee should be made binding and also ensure that no further inquiries be initiated. Otherwise, there will be committee-after-committee and the women are deprived of justice.

Sir, I have a strong objection to Clause 14 of the Bill, which seeks to punish false or malicious complaints. I fear that cases of harassment will fall between the cracks of the new Bill. Here, I would like to give an example. A woman is working in an advertising company, and she was asked by the Director to prove the sexual favour that her supervisor had verbally demanded. Now, Clause 14 of the Bill asks for evidence of such acts that often would be done in an implicit or clandestine manner. How can she produce evidence in such a case? Besides, if she fails to prove harassment, she would be prosecuted. Certain forms of sexual harassment cannot be proved beyond reasonable doubt as may be possible with physical injury or other crimes. In such a situation, it is very unfortunate that the lack of proof of a crime makes the complainant liable for punishment.

Lastly, Sir, according to the Workplace Sexual Harassment Survey conducted by Centre for Transforming India, a non-profit organisation, among 600 female employees working in the IT sector across India, as many as 50% women reported to have been subjected to abusive language, physical contact or had superiors seeking sexual favours; 47% female employees did not know where to report sexual harassment and 91% did not report for fear of being victimised.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much. You can lay it on the Table.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: Sir, a victim fears reporting a crime speaks volumes of realities of women's lives. To add a clause of prosecution for women in the Bill is a definitive strategy to strengthen women's fear and ensure silence.

Sir, finally, I would like to conclude by saying that this Bill should be taken very seriously. We are passing so many Bills, but they are not properly implemented. We are passing so many Bills, but they are not taken seriously. Sir, I support the Bill brought forward by the hon. Minister.

श्री राम कृपाल यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की अनुमति प्रदान की है। इस देश में महिलाओं की संख्या आधी है और इस आधी आबादी के बीच में जो काम-काजी महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यह कानून लाया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। महोदय, यौन उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि देश के सामने एक बड़ी समस्या है। कई वर्षों की लगातार छान-बीन के बाद, मंथन के बाद और कई तरह के सुधारों के बाद इस कानून को सदन में लाया गया है, मगर मैं समझता हूं कि कानून तो पहले से भी हैं, जैसे कि चर्चा भी की गई है, मगर उस कानून के रहते हुए भी महिलाओं के उत्पीड़न में कमी नहीं आई है, बल्कि यह धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। देश तब शर्मसार हो गया, मानवता हिल कर रह गई, जब दिल्ली में दामिनी केस हुआ। पूरे देश के मानव समाज का सिर झुक गया। उसके ठीक बाद, गहन विचार-विमर्श होने लगा कि आखिर ऐसे कौन से कानून को स्वरूप दिया जाए, कौन से ऐसे प्रावधानों को लाया जाए, ताकि लोगों के मन में डर और भय हो।

मगर मुझे आश्चर्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हम सब लोग जितना ज्यादा चिन्तित हैं, उतना ही दरिंदगी करने वाले लोगों की दरिंदगी बढ़ती जा रही है। अगर आप विभिन्न राज्यों के समाचार पत्रों को देखेंगे, गृह मंत्रालय के पास भी प्रति वर्ष रिपोर्ट आती है, तो आप पाएंगे कि इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आज महिलाएं असुरक्षित हैं। भारतीय सभ्यता और सांस्कृति यह रही है कि हम महिलाओं की बहुत कद्र करते हैं, आदर करते हैं और महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं। पहले जब हमारा समाज अनपढ़ था, अशिक्षित था, तो हम महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे, जिसकी वजह से महिलाओं के कामकाजी होने की बात छोड़िए, ठीक से उनकी पढ़ाई-लिखाई भी नहीं होती थी, घर के चौखट तक उनकी सीमाएं होती थीं, घर में खाना बनाओ और वहीं अपना जीवन बिताओ। पर जब हमारा समाज विकसित हुआ, हमारी सोच में बदलाव हुआ, तो कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी, पढ़ाई-लिखाई करने वालों की संख्या बढ़ी। मगर मैं समझता हूं कि आज निश्चित तौर पर लोगों के मन में असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ रही है। कानून बन रहे हैं, लेकिन इच्छाशक्ति न हो, नीति साथ न हो, तो नियम कानून तो

बनते रहेंगे, मगर इच्छाशक्त के अभाव में अगर कानून का इम्प्लिमेंटेशन नहीं होगा, तो कानून का कोई मतलब और मकसद नहीं निकलेगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी एक अच्छा विधेयक लेकर आई हैं, यह पास भी हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा, लेकिन हमारी जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं, जिनसे मानव समाज खास तौर से ज्यादा ग्रसित हो रहा है, जब तक हम इस मानसिकता को बदलने का काम नहीं करेंगे, जब तक सोच में बदलाव नहीं आएगा, सामाजिक परिवेश में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम जितने भी कानून बना लें, यौन शोषण होता रहेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहेगा, उत्पीड़न बढ़ता रहेगा। इसलिए कानून बने, मगर सदन एक महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा कर रहा है, तो हमें इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो सोच लगातार बढ़ती जा रही है, अपराध की प्रवृत्ति, दरिंदगी की प्रवृत्ति, यौन शोषण की प्रवृत्ति, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, हम इनको कैसे रोकें। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल हे, जो समाज, सदन और पूरे देश के सामने है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है। इस सोच में बदलाव कैसे आएगा, यह बहुत ही जरूरी है। हमारे देश की आबादी लगातार बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि केवल कानून ही सक्षम नहीं है।

मैं एक बात और निवेदन करूंगा। कानून तो बन जाते हैं, मगर उनमें समय सीमा निर्धारित नहीं है। आपने कानून बना दिया, अगर स्पेशल कोर्ट का निर्माण नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि इसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, अनवरत समय लगेगा और जो उत्पीड़ित महिला है, उसके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप स्पेशल कोर्ट के निर्माण के बारे में सोंचे। चूंकि कानूनी तौर पर इतनी ज्यादा प्रक्रियाएं हैं कि उन प्रक्रियाओं को एडॉप्ट करते-करते सालों-साल लग जाते हैं और फिर कानून का मतलब नहीं होता है।

बहन प्रभा ठाकुर जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि जो बलात्कार के केसेज़ हो रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यह एक बड़ा अपराध है। यह हत्या से कम बड़ा अपराध नहीं है। जिसके साथ यह घटना होती है, उसकी जिन्दगी तबाह हो जाती है, उसका परिवार तबाह हो जाता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वे महिलाएं समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती हैं। खासतौर पर अब तो यह देखा जा रहा है कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ, मैं अपने स्टेट के कई उदाहरण दे सकता हूं, मेरे पास समय नहीं है, मगर मैं यह कह रहा हूं कि 5-5 साल, 6-6 साल की जो बच्चियां हैं, जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, उनके साथ भी सामूहिक बलात्कार हो रहा है और उनकी हत्या हो रही है। हमारा समाज कहां जा रहा है? हम किस सोच की ओर जा रहे हैं? हमारी सोच में किस तरह की गिरावट आई हैं? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कानून को जरूर इम्प्लिमेंट करें, मगर उसके साथ-साथ अगर हमारी सोच में बदलाव नहीं आएगा, तो हम चाहे जितना भी कानून बना लें, मैं समझता हूं कि यह इस कानून से रुकने वाला नहीं है।

[श्री राम कृपाल यादव]

मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, मैं एक अन्तिम बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। एक सवाल और भी है। माननीय मंत्री जी आप इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि अगर हम बहुत सारे सख्त कानून लाते हैं, तो कहीं वे कामकाजी महिलाएं, जो अपने पेट के लिए रोटी की जुगाड़ में काम करने के लिए मजबूरीवश जा रही हैं, घर में भी काम करना है, बाहर भी काम करना है, तो क्या इस कानून से उन कामकाजी महिलाओं के कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा और क्या उन महिलाओं को काम करने से रोका जाएगा?

यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसकी तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो आप कानून बनाते जाइए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर महिलाओं को कामकाज से दूर रखने का काम किया जाएगा तो उनके लिए रोजी-रोटी की एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि जिन बिन्दुओं को माननीय सदस्यों ने और हमने उठाया है, निश्चित तौर पर समय रहते हुए उनको कानून के रूप में इम्प्लिमेंट किया जाए। इस बिल में यह प्रावधान भी जरूर होना चाहिए कि विशेष न्यायालय व्यवस्था हो, ताकि समय सीमा के अन्दर इस प्रकार के केसिज़ का निपटारा हो जाए और अपराधियों को सजा मिल सके। धन्यवाद।

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, on behalf of Dravida Munnetra Kazagham and on behalf of the women of this country, I rise to support The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2012. This Bill has come very late, at least, fifteen years late after the landmark judgement by the Supreme Court in the Vishakha case. But it has finally come and I urge the Members of the House to support it. While supporting this Bil, I would also like to make some observations which, I hope, will be taken into consideration.

First, the Bill gives the definition for 'aggrieved women' under Clause 2(a). It currently excludes the women, like, agricultural workers and the women working at places, like, armed forces, police, woman students and woman staff of schools, universities, coaching centres and other educational institutions. It is very important that we include these women. These women constitute a large chunk of working women in this country. It has to be included under the purview of this Bill to have more meaning. Also, the definition of 'sexual harassment' under Section 2, includes any one or more of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication) namely:- (i) Physical contact and advances; or (ii) a demand or

request for sexual favours; or (iii) making sexually coloured remarks; or (iv) showing pornography; or (v) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature." Here, the catch words are 'unwelcome physical'. I would like to suggest that when we determine 'unwelcome', it should actually be determined by the victim, and not by any Committee or by anybody outside. Even Justice Verma Commission has also recommended it. It is the victim who has to decide what 'unwelcome gestures' or 'unwelcome activities towards her' are. If we do not do that then, again, it will become another way to harass a woman or to find other ways to get out. So, this should be taken into consideration. Then, I come to clause 9, how a complaint of sexual harassment shall be made. It says, "Any aggrived woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at a workplace to he Internal Committee if so constituted, or the Local Committee, in case it is not so constituted, within a period of three months from the date of incident and in the case of series of incidents, within a period of three months from the date of last incident." Here, I would like to bring to your notice two specific things. Firs, when we are taking about agricultural workers or other workers, not many of them are capable of giving a written complaint. Also, not everybody is really comfortable in writing or giving a written complaint. So, it should also include 'oral complaints'.

The aggrieved persons or the victims should be able to go and give their complaints orally. Insisting on making a complaint in writing by the victim, actually, will be unfair to a large population of women. We all know that still, in this country, women's education has not reached the desired level. So, we have to take this aspect into consideration. With regard to limiting this to a period of three months, Sir, you know of social pressures in the country and how the society looks at a woman who makes a complaint of sexual harassment against anybody. So, it is not very easy for a woman to convince herself to make such a complaint. Not many of them complaint at the first incident. Unless it becomes repeated and intolerable, no woman will make a complaint. So, if you are limiting it to three months, then you are taking away the right of many women going and making the complaint. This law has been brought forward to protect them. But by limiting the time to three months, you are, actually, taking away a lot than what you are giving. Sir, one more thing which I would like to bring to your notice is this. Clause 10(1) of the Bill says, the Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee, may, before initiating an

[Shrimati Kanimozhi]

inquiry under section 11 and at the request of the aggrieved woman take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation, provided that no monetary settlement shall be made as a basis of conciliation. This seems to be a direct violation of the Vishaka judgement. Moreover, how can there be a conciliation in a case like this? Law cannot encourage this. This is not a settlement, this is not a business contract or anything else where a conciliation can be achieved over the table. This is, actually, a violation. There can be no conciliation and I don't think the law should even mention this or take into account conciliation.

Fourthly, Sir, in the one hand, this legislation will bring a great empowering effect to the working woman across the country, on the other, clause 14 seems to be working against the purpose of this legislation. Clause 14 relates to punishment for false or malicious complaint and false evidence. It says, "Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document..." Then, they can take action against this woman who has made the complaint. I humbly submit, Sir, that this provisions will end up nullifying the very purpose of this law. We know how society works against women. They would rather not hear about it and no company would rather hear about sexual harassment within their campus against women. If you are, actually, going to turn the tables against the women who are finally coming forward to make a complaint, then, there are other was in law to take care of this. Like, if you are giving false evidence with a malicious intent, there are other sections in law to take care of it. So, if you are going to include this in this Bill, actually, there is chance to turn the whole thing against the woman who is making a complaint. So, I kindly submit that this has to be taken into consideration seriously. Thank you, Sir.

SHRIMATI RENUBALA PRADHAN (Odisha): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

I welcome the Bill as the women in their workplaces are harassed severaly

despite several existing provisions. A number of working class women are being harassed, sexually-exploited in different forms by their higher bosses in the working places. Many of them do not ventilate their plights either due to social taboo or fear of their higher officers.

I urge the Ministry to make such provision by constituting separate independent forum to ventilate the grievances particularly related to the sexual harassments of the women at their workplaces in district and block levels. The independent forum should be constituted only with woman members so that the victimized women can ventilate their grievances properly.

Secondly, I also urge the Minister to ask each Government, semi-Government and private offices and institutes to constitute a cell to look into the grievances of the sexual harassment of the women at their workplace.

Although the Government had directed it some years ago, the same was not materialized in several offices. It should be made mandatory. Sir, the Government should make it clear in the Bill as to how it would deal with the Sexual harassment of those women who work in the unorganized sectors. It is seen that the females who are working in the unorganized sectors. It is seen that the females who are working in the unorganized sectors are more harassed than the women working in the organized sector. When they raise their voice, they lose their job in the organization.

In some cases, the police also does not register the cases under the provisions of the IPC when they go to police stations.

When the Government want to provide equal opportunity to the womenfolk and to get rid of the discrimination against the women, I urge he Government to incorporate some of these provisions so that the working women in both the organized and unorganized sectors can ventilate their grievances without fear and with an expectation to get justice. Sir, I want to give some suggestions in this regard. In order to address the problem of assault on women, Special Fast Track Courts should be constituted throughout the nation, at least, at all District and Sub-Divisional levels so that the victimized women can seek quick justice. Thank you, Sir.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश): धन्यवाद, सर। सर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो "महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2012" लाया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। महोदय, आदि काल से इस देश के अंदर महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता रहा है। इतने वर्षों के बाद, आज भी स्थितियां वहीं की वहीं हैं। इस पुरुष प्रधान देश में आज अगर हम देश की स्थिति उठा कर देखते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं, जो प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में हैं, लेकिन जब हम मेल एण्ड फीमेल रेशयों देखते हैं, तो उनकी स्थिति देख कर हमें लगता है कि आज भी हमारी धारणा वहीं की वहीं है। कभी पुराणों में कहा जाता था, "यत्र पूज्यते नार्यस्तु, तत्र रमन्ते देवता:", और कहीं यह भी कहा है, "शुद्र पशुनारी, ये सब तारण के अधिकारी कहीं तो नारी की पूजा की है और कहीं नारी को अवमानना की दृष्टि से देखा है। जब चाहा उसको पैर की जूती समझा और जब चाहा उसको सिर पर उठाया है। हमारे यहां कहा भी गया है कि देवताओं के आगे देवियों के नाम होते हैं, जैसे-राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-नारायण आदि। इस देश की आज़ादी में भी रानी झांसी और रानी दुर्गावती जैसी महिलाओं ने समय-समय पर अपनी प्राथमिकता और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। लेकिन, इसी देश में महिलाओं के प्रति एक मानसिकता यह है कि शुरूआत में ही, यानी गर्भावस्था में ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है और जब लड़की पैदा होती है, तो घर के अंदर ही भाई और बहन में जो एक द्वेष रहता है, वह भी हमें इसी जगह पर देखने-सुनने को मिलता है।

आज मैं यहां यह कहना चाहती हूं कि हम आदरणीय राजीव गांधी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर भी लोकल बॉडीज़ में 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया था। उन्होंने महिलाओं के मान-सम्मान में वृद्वि करते हुए पंचायती राज के माध्यम से, स्थानीय शासन के माध्यम से इस देश के अंदर उन्हें जो एक सम्मान दिया था, उसके लिए हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने उनको सत्ता में जो एक भागीदारी दी थी, उसका एक अलग महत्व है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आजकल महिलाएं जो कामकाज कर रही हैं, वह उनकी मजबूरी है, उनकी आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से इस देश के अंदर उनकी मजबूरी है, उनकी आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से इस देश के अंदर उनका हरैसमेंट हो रहा है, उसे सभी लोग भली-भांति जानते हैं। पुरुष वर्ग अपनी सत्ता खोने के कारण समय-समय पर उनके अंदर जो इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उसके कारण वे अपने आपको इनसेक्योर फील करते हैं और उसकी वजह से कहीं न कहीं महिलाओं पर अत्याचार और हरैसमेंट होता रहता है। ...(व्यवधान)... मैं सभी पुरूषों की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं कुछ पुरूषों की बात कर रही हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि नज़मा जी ने कहा कि वर्कप्लेस पर जो सेक्सुअल हरैसमेंट की बात की गयी है, उसके साथ-साथ वहां मानसिक और शारीरिक रूप से भी जो प्रताड़ना मिलती है, उनके ऊपर भी माननीय मंत्री जी को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले ही गुड़गांव के अंदर एक डॉक्टर दम्पत्ति ने एक 10-12 साल की लड़की को बिना खाना-पीना दिए अपने घर के अंदर कैद करके रखा था। तो, इस तरह के शारीरिक और मानसिक अत्याचार भी लड़कियों और महिलाओं के ऊपर होते रहते हैं। अभी हाल में दिल्ली की जो घटना हुई, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और उससे देश के अंदर एक जुनून-सा उठ खड़ा हुआ था। मेरा इसमें यही निवेदन है कि देश की लोकसभा और विधान सभाओं में कानून तो बहुत बनते हैं, अमेंडमेंट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनका सही रूप से क्रियान्वयन हो। हमारे एक्ट में, हमारे आईपीसी में भी बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है।

यहां पर यह भी कहा गया है कि खास कर इस तरह के जो केसिज़ होते हैं, उनमें समय पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। हम लोग चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और वहां समय पर रिपोर्ट नहीं लिखे जाने से उनकी इन्वेस्टिगेशन लम्बी चलती है। इन्वेस्टिगेशन समय पर प्रॉपर्ली तरीके से न होने से जब कोर्ट्स में लम्बे-लम्बे प्रकरण चलते हैं, तो उसके कारण केस डाइल्यूट हो जाते हैं और कहीं न कहीं वे केस धनबल और भुजबल से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस देश की ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है। वहां पर कृषक महिलाएं होती हैं, जो खेतों में मजदूरी करती हैं, जिनका हरैसमेंट सबसे ज्यादा होता है। मेरे ख्याल से इस बिल के अंतर्गत वे नहीं लायी गई हैं। उनमें ज्यादातर संख्या मारे महिला कृषक मजदूरों की होती है, जिनको इसमें लाने की बहुत आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि ये यहां पर यह बिल लेकर आयी हैं। आप इसमें बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स कर रही हैं और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आई हैं, लेकिन इसमें आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि अगर इनका क्रियान्वयन प्रॉपर्ली तरीके से होगा, तो मैं समझती हूं कि देश में महिलाओं के मान-सम्मान और इज्जत की रक्षा सुचारू रूप से हो सकेगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

———————